किया जा रहा है इसके परिणामस्वरूप 7वीं योजना के दौरान चने की 17, अरहर की 7, मूंग की 8, मटर की 5, मसूर की 4 किस्में और उड़द, मोठ और लोबिया प्रत्येक की दो-दो किस्में विकसित की गई हैं । इन किस्मों के प्रजनक आधारों और प्रमाणीकृत बीजों का उत्पादन और वितरण प्रारंभ किया गया है ।

उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, आन्ध्र प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में अरहर, मूंग, उड़द और लोबिया की अल्पावधि किस्मों को आरंभ करके बहुसस्य पद्धति के संवर्धन में ये किस्में सहायक सिद्ध हुई हैं।

**खाद्य तेलों की कमी**

1135. **सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :**
**श्री राम जेठमलानी :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 31 अक्तूबर, 1990 के "फाइनैन्सियल एक्सप्रेस में "एडीबुल आयल शार्टेज टू टच 13 एल.टी. इन 1990-91" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस वर्ष देश में खाद्य तेलों के उत्पादन के बारे में सरकार के क्या अनुमान हैं ;

(ग) क्या सरकार ने इस वर्ष देश में खाद्य तेल की खपत के बारे में कोई मूल्यांकन किये हैं ; और

(घ) सरकार दालों की मांग और पूर्ति के बीच के अंतर को कम करने के लिये क्या कदम उठाने का विचार रखती है ;

**कृषि मंत्रालय में और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयन्ती लाल वीरचन्द भाई शाह)** : (क) जी, हां ।

(ख) खरीफ तिलहनों का उत्पादन अनुमानतः 87 लाख मीटरी टन है । रबी में उत्पादन की आशा अनुकूल है परन्तु वर्तमान चरण पर पक्के अनुमान देना संभव नहीं है । इसलिये इस समय यह कहना संभव नहीं है कि इस वर्ष देश में खाद्य तेलों का उत्पादन कितना होगा ।

(ग) तेल वर्ष 1990-91 में देश में खाद्य तेल की मांग करीब 60 लाख मीटरी टन होने की आशा है ।

(घ) सरकार, तिलहनों के उत्पादन और खाद्य तेल की उपलब्धता बढ़ाने के लिये तिलहन उत्पादन कार्यक्रम क्रियान्वित कर रही है । तिलहन परिसंस्करण और निष्कर्षण की क्षमता बढ़ाने के लिये प्रयास किये जा रहे हैं । इस अंतर को कम करने के लिये खाद्य तेल के आयात पर भी विचार किया गया है ।

**दिल्ली में वनस्पति के मूल्यों में वृद्धि**

1136. **श्री बलराम सिंह यादव :**
**डा० जिनेन्द्र कुमार जैन :**

क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 18 अक्तूबर, 1990 के हिन्दुस्तान टाइम्स में "शार्प इनक्रीज इन वनस्पति प्राइसेस" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है, और यदि हां, तो दिल्ली में जुलाई, 1990 से अक्तूबर, 1990 के बीच वनस्पति के मूल्यों में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि 1990 में त्यौहारों के मौसम के दौरान वनस्पति के दामों में अत्यधिक वृद्धि हुई है ;

(ग) यदि हां, तो दिल्ली में अक्तूबर, 1990 में वनस्पति के मूल्य क्या थे ; और

(घ) मूल्यों में कमी लाने के लिए सरकार द्वारा क्या हाल में प्रशासनिक कदम उठाए गए हैं ?

**खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सरवर हुसैन)** : (क) जी हां, जुलाई, 1990 से अक्तूबर, 1990 तक दिल्ली में लोकप्रिय ब्रांडों के वनस्पति के मूल्यों में लगभग 17 प्रतिशत वृद्धि हुई थी ।

(ख) जी हां ।

(ग) दिल्ली में रथ और डालडा वनस्पति की 1 कि. ग्रा. की थैली के मूल्य दिनांक 31 अक्तूबर, 1990 को क्रमशः 38.65 रुपये और 39.30 रुपये थे ।

(घ) सरकार द्वारा कीमतों को कम करने के लिए उठाए गए कुछ प्रशासनिक कदम इस प्रकार हैं :—

1. वनस्पति के विनिर्माण में लघु/गैर-परम्परागत तेलों के प्रयोग पर उत्पाद शुल्क में छूट दी गई है ;

2. थोक और खुदरा विक्रेताओं के पास हाइड्रोजनित वनस्पति तेलों की स्टाक सीमा घटाई गई है ;

3. उत्पादकों के पास खाद्य तेलों और वनस्पति की स्टाक सीमाएं घटा दी गई है ;

4. कम की गई स्टाक सीमाओं को लागू करने के लिए राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे नियमित आधार पर जमाखोरी विरोधी अभियान चलाएं ।

**दिल्ली हाउसिंग फाइनेंस सोसाइटी समिति द्वारा सहकारी आवास समितियों को ऋण**

1137. **श्री बलराम सिंह यादव :**
**श्री राम जेठमलानी :**

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 13 दिसम्बर, 1990 को जनसत्ता में "जब कर्ज ही नहीं मिलेगा तो मकान कहां से बनेंगे" शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने हाल में दिल्ली की लगभग 400 सहकारी आवास समितियों को भूमि के आवंटन के बारे में अपनी योजना को कार्यान्वित किया है जब कि दिल्ली हाउसिंग फाइनेन्स सोसाइटी ने आवास निर्माण के लिये केवल 250 करोड़ रुपये की ऋण राशि ही निर्धारित की है ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ऋण की राशि बढ़ाने का विचार रखती है ;

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और प्रत्येक समिति को हाउसिंग फाइनेन्स सोसाइटी द्वारा ऋण की कितनी-कितनी राशि दिए जाने की संभावना है ?

**शहरी विकास मंत्री (श्री दौलत राम सारण)** : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने हाल ही में 423 सहकारिता सामूहिक आवास समितियों को पप्पनकलां/नरेला में भूमि आवंटन के लिए प्रस्ताव-पत्र भेजे हैं ।

दिल्ली सहकारी आवास वित्त समिति लिमिटेड ने, जो कि सहकारी सामूहिक आवास समितियों की ऋण आवश्यकताएं पूरी करता हैं, आठवी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान वित्त प्रदान करने वाली संस्थाओं से निधि की पूर्वानुमानित उपलब्धता के आधार पर 250 करोड़ रुपये की राशि उद्दिष्ट की है । सहकारी सामूहिक आवास समितियों की ऋण आवश्यकता पूरी करने वाली यह अकेली संस्था नहीं है । जीवन बीमानिगम, आवास वित्त निगम, हुडको, एच. डी. एफ. सी., कैन फाइनेन्स होम बैंक इत्यादि जैसी अन्य संस्थाएं भी हैं जो सहकारी सामूहिक आवास समितियों की ऋण आवश्यकताओं को पूरी करती हैं । सरकार ने भी देश में आवास वित्त संस्थाओं के कार्यकलापों में